4. भूमिगत अर्थव्यवस्था (Underground Economy)

पूर्ति पक्षधरों का अन्य महत्त्वपूर्ण तर्क यह है कि कर की अधिक सीमान्त दरें लोगों को भूमिगत अर्थव्यवस्था (जिसे भारत में सामान्यतः ब्लैक मार्किट या समानान्तर अर्थव्यवस्था कहा जाता है) में कार्य करने को प्रात्साहित करते है जहाँ उनकी आय का आयकर विभाग द्वारा पता नहीं लगाया जा सकता है। भारत में यह भूमिगत अर्थव्यवस्था बहुत विशाल है। केवल व्यक्तिगत व्यवसायी ही आय करों का अपवंचन नहीं करते बल्कि निगमित फर्मों ने भी अपने लाभी पर करों का अपवंचन करने के अनेक अवैधानिक तरीके अपना रखे हैं। केवल व्यक्तिगत आय तथा कम्पनी लाभों पर करों का भुगतान ही नहीं बल्कि उत्पादन शुल्क तथा बिक्री कर का भी पूर्ण रूप से भुगतान व्यक्तियों तथा कम्पनियों द्वारा नहीं किया जाता है। पूर्ति पक्ष की विचारधारा के समर्थन में ही हमारे वित्त मन्त्री पी. चिदाम्बरम ने प्रायः करों में कमी के पक्ष में तर्क दिया है। उनके अनुसार कर की अपेक्षाकृत कम दर कर अनुपालन में वृद्धि करेगी जो लोगों द्वारा घोषित आय की धनराशि में वृद्धि करेगी। इस प्रकार पूर्ति पक्षीय अर्थशास्त्री मानते हैं कि करों में कमी वस्तुतः लोगों को करों का अपवंचन करने तथा भूमिगत अर्थव्यवस्था में काम करने से हतोत्साहित करके कर-आय में वृद्धि करेगी।

5. कर आय तथा लाफर वक्र (tax revenue and laffer curve)

एक प्रमुख पूर्ति पक्ष अर्थशास्त्री आर्थर लैफर ने तर्क दिया कि कर की अपेक्षाकृत कम दरें कर-आय में वृद्धि के साथ पूर्णतः संगत होती हैं। उन्होंने कर की दरों तथा एकत्रित कर की कुल धनराशि के मध्य सम्बन्ध को एक वक्र की सहायता से प्रदर्शित किया है जिसे उनके नाम के आधार पर ही लैफर वक्र (Laffer curve) का नाम दिया गया है। लैफर वक्र यह प्रदर्शित करता है कि एक निश्चित सीमा के बाद कर की दरों में वृद्धि कर-आय में कमी कर सकती है क्योंकि इसका कार्य, बचत तथा विनियोग की प्रेरणाओं पर बुरा प्रभाव पड़ता है। एक निश्चित सीमा से अधिक कर की दरें उत्पादकता के विरुद्ध सिद्ध होती हैं क्योंकि वे कार्य, बचत तथा

Ravi Shankar Ray

विनियोग को हतोत्साहित करके श्रम की पर्ति तथा पूंजी संचय को कम कर देती हैं। अतः कर की ये ऊँची दरें राष्ट्रीय उत्पादन तथा आय को कम करती हैं।

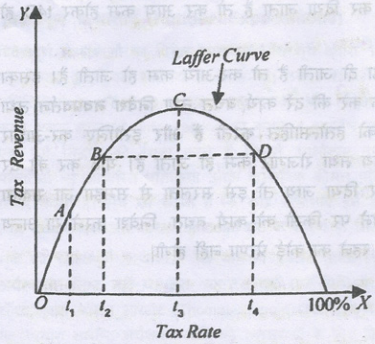

रेखाकृति 26.2 लैफर वक्र : कर की दर तथा राजस्व में सम्बन्ध

स्मरणीय है कि एकत्रित कुल कर-आय (TR), t द्वारा व्यक्त कर की दर तथा Y द्वारा व्यक्त कुल आय के गुणनफल के

या दोती है। अतः कुल कर आय TR = tY । लैफर के अनुसार जब कर की दर t को एक सीमा से अधिक बढ़ा दी जाती है तो कर-वृद्धि के परिणामस्वरूप राष्ट्रीय उत्पादन तथा आय इतनी कम हो जाती है कि कुल कर-आय tY कम हो जाती है | चित्र 26.2 में लैफर वक्र खींचा गया है। लैफर वक्र मूल बिंदु से प्रारंभ होता है जिसका अर्थ है कि जब कर का दर शुन्य होती है तो कुल कर आय भी शून्य होती है। C बिंदु तक लैफर वक्र उठता हुआ है जो यह प्रदर्शित करता है कि जैसे-जैसे कर दी दर बढ़ कर t3 , होती है, एकत्रित कर आय में वृद्धि होती है। किन्तु यदि कर की दर को t3 से अधिक बढाया जाता है, लैफर वक्र नीचे की ओर मुड़ने

Ravi Shankar Roy

लगता है जो यह प्रदर्शित करता है कि कर की दर के t3 से अधिक बढ़न के साथ कर-आय कम हो जाती है जिसके कारण की व्याख्या पहले की जा चुकी है। t3 कर की दर पर एकत्रित कर आय t3C अधिकतम होती है| उदहारण के लिए यदि कर की दर को t3 से बढाकर t4 कर दिया जाता है तो कर आय कम होकर t4D हो जाती है|

जब कर की दर एक का बढ़ा दी जाती है तो कर-आय कम हो जाती है। इसका कारन है कि अपेक्षाकृत अधिक कर की दरें कार्य, बचत तथा **निवेश नवप्रवर्तन** तथा व्यावसायिक जोखिम उठाने को हतोत्साहित **करती हैं और** इसीलिए कर-आधार (tax base) अर्थात् राष्ट्रीय आय तथा रोजगार कम हो जाता है। यदि कर की दर को **बढ़ाकर 100 प्रतिशत** कर दिया जाय तो इसे सरलता से समझा जा **सकता है**।100 प्रतिशत कर की दर होने पर किसी को कार्य, बचत. निवेश करने या अन्य आर्थिक गतिविधियों में व्यस्त रहने का कोई प्रेरणा नहीं होगी|

Ravi Shankar Roy